पैन इंडिया कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता

आज़ादी का अमृत महोत्सव

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

पृष्ठभूमि

- दिशा योजना के तहत, कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का अब अखिल भारतीय स्तर पर विस्तार किया गया है।
- यह एक बहु-हितधारक, प्रगतिशील और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है जो कानूनी अधिकारों, अधिकारों और प्रासंगिक कानूनों पर महत्वपूर्ण जानकारी और जागरूकता के लिए कमजोर वर्गों को सक्षम करने के लिए नवीन विचारों, उपकरणों और सरलीकृत पद्धति को एकीकृत कर रहा है।

उद्देश्य

- कार्यक्षेत्र और वितरण के विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग
- विशेषज्ञ संस्थाओं के साथ साझेदारी करके विधिक साक्षरता को मुख्यधारा में लाना
- मौजूदा जमीनी स्तर/फ्रंटलाइन कार्यबल/स्वयंसेवकों का क्षमता निर्माण और उपयोग
- प्रभावशीलता को मापने के लिए संकेतक विकसित करना
- समवर्ती मूल्यांकन और आवधिक मूल्यांकन

भागीदार एजेंसियां

1. **भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली**
   राष्ट्रीय स्तर पर विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन।
2. **नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बंगलूरू, कर्नाटक**
   "डिजिटल कानूनी साक्षरता-प्रसार और आकलन"
3. **राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश**
   "डिजिटल विधिक साक्षरता – डिजाइन, विकास, प्रबंधन और परीक्षण –ई–न्यायगंगा" ।
4. **राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू), नई दिल्ली**
   "उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र आयोजित करना" (अधिकारों का ज्ञान प्रगति की पहचान है) ।
5. **अरुणाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण (एपीएसएलएसए), इटानगर, अरुणाचल प्रदेश**
   "औपचारिक न्याय प्रदायगी प्रणाली पर गांव बुरास और गांवबुरियों की क्षमता निर्माण द्वारा "पारंपरिक ग्राम परिषद प्रणाली और भारत के औपचारिक कानूनों की प्रथागत प्रथाओं के बीच तालमेल" ।
6. **सिक्किम राज्य महिला आयोग (एसएससीडब्ल्यू), गंगटोक, सिक्किम**
   "कर्मचारियोंए छात्रों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों जैसे विभिन्न हितधारकों के लिए "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013, घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षण अधिनियम, 2005 मानव तस्करी रोध" पर प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम ।
7. **मनोचिकित्सा विभाग, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा विज्ञान संस्थान (जेएनआईएमएस), इम्फाल ईस्ट, मणिपुर**
   "प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र आयोजित करके "बाल यौन शोषण के खिलाफ मीडियाकर्मियों, छात्रों, हितधारकों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण"।
8. **सेंटर फॉर कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स सोसाइटी (सीकोडेकॉन), जयपुर, राजस्थान**
   "राजस्थान के 5 आकांक्षी जिलों में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता को बढ़ावा देना" ।.
9. **शैडो एडवरटाइजिंग एण्ड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर, ओडिशा**
   ओडिशा राज्य में "अभिनव विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम" ।.
10. **यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी (यशदा), पुणे, महाराष्ट्र**
    महाराष्ट्र की विन्हित ग्राम पंचायतों में "विधिद्रूत को बढ़ावा देना" ।.
11. **विधि अनुसंधान संस्थान (आईएलआरआई), गुवाहाटी, असम**
    "भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रथागत कानूनों का दस्तावेजीकरण" ।.
12. **बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान (बिपर्ड), पटना, बिहार**
    ग्रामीण बिहार में विन्हित किए गए "विधिमित्रों को बढ़ावा देना" ।.
13. **अब्दुल नजीर उप राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, मैसूर, कर्नाटक**
    (सैटकॉम) प्रौद्योगिकी के माध्यम से "पंचायत ग्रामीण संस्थान (पीआरआई) विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम का प्रशिक्षण और संवेदीकरण"।
14. **मेघालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिलांग, मेघालय**
    सामुदायिक मध्यस्थता के माध्यम से न्याय तक पहुंच बढ़ाने पर परियोजना

अंतर-मंत्रालयी अभिसरण

पंचायती राज
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

- 4 लघु फिल्में विकसित की गई हैं। इन लघु फिल्मों का पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रसार किया जा रहा है।

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY

- न्याय विभाग द्वारा प्रदान की गई कानूनी साक्षरता सामग्री शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को शिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई स्कूल शिक्षा के वेब पोर्टल दीक्षा (स्कूली शिक्षा के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा) पर अपलोड की गई है।

सामाजिक-कानूनी मुद्दों पर वेबिनार

न्याय विभाग द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय-स्तर के सामाजिक.कानूनी मुद्दों पर कानून जागरूकता वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया है। अब तक न्याय विभाग ने सोलह वेबिनार आयोजित किए हैं। इन सोलह राष्ट्रीय-स्तरीय वेबिनारों के माध्यम से, न्याय विभाग 3.87 से अधिक प्रतिभागियों तक पहुँच चुका है।

22 सितंबर 2021 को "घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम" 2005 पर आयोजित वेबिनार, 48,299 प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

14 नवंबर 2021 को "बाल अधिकारों पर आयोजित वेबिनार" 17,644 प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

26 नवंबर 2021 को "मौलिक कर्तव्य" विषय पर आयोजित वेबिनार, 24,082 प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

7 जनवरी 2022 को "गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994" पर आयोजित वेबिनार, 15,080 प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

18 फरवरी 2022 को "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" पर आयोजित वेबिनार, 19,158 प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

8 मार्च 2022 को "भारत में लैंगिक न्याय" पर आयोजित वेबिनार, 35,332 प्रतिभागियों से संपर्क किया गया।

25 अप्रैल, 2022 को "कानून के साथ संघर्ष में बच्चे" पर आयोजित वेबिनार, 20,207 प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

27 मई, 2022 को "चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन" पर आयोजित वेबिनार, 24,715 प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

29 जून, 2022 को "मानव तस्करी" पर आयोजित वेबिनार, 30,627 प्रतिभागियों से संपर्क किया गया ।

31 अगस्त, 2022 को "वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार" पर आयोजित वेबिनार, इसे 13,255 लाभार्थियों से संपर्क किया गया ।

28 अक्टूबर 2022 को "भारत में साइबर अपराध" पर आयोजित वेबिनार 30,442 लाभार्थियों तक पहुंचा ।

25 नवंबर 2022 को "संवैधानिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों" पर आयोजित वेबिनार 37,481 लोगों तक पहुंचा।

27 दिसंबर, 2022 को "भारत में विकलांग व्यक्तियों" के अधिकार पर आयोजित वेबिनार 16,612 प्रतिभागियों तक पहुंचा।

30 जनवरी 2023 को "भारत में विचाराधीन कैदियों" के अधिकार पर आयोजित वेबिनार 17,960 कार्यकर्ताओं तक पहुंचा।

6 मार्च 2023 को "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और उनके अधिकारों का संरक्षण" पर आयोजित वेबिनार 29,851 प्रतिभागियों तक पहुंचा।

28 मार्च 2023 को "उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण" पर आयोजित वेबिनार 21,143 प्रतिभागियों तक पहुंचा।

12 जून, 2023 को "भारत में बाल श्रम" पर आयोजित वेबिनार 25,133 प्रतिभागियों तक पहुंचा।

समाचार में पैन इंडिया कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता

Union Justice Dept holds awareness campaign on Consumer Protection Act

ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಪಂ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ

Awareness drive on consumer rights & sexual harassment

STATESMAN NEWS SERVICE

KORAPUT, 11 JANUARY

एनएलआईयू के 'ई-न्याय गंगा' से जानें क्या है सूचना का अधिकार

जानें अपने अधिकार

ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ: ಸಂತೋಷ ಬಿರಾದರ ಪಾಟೀಲ ಇ.ಓ.

ସମ୍ବାଦ

କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା

ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆଇଇସି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

सभ्य समाज में किसी तरह की हिंसा स्वीकार नहीं, जागरूकता ही उपाय

IEC awareness campaign on sexual harassment at workplace

STATESMAN NEWS SERVICE

BHUBANESWAR, 25 JANUARY

SEXUAL HARASSMENT: NOT IN MY WORKPLACE

विधिक साक्षरता जागरूकता पर जिला स्तरीय बैठक

Workshop held on legal literacy and awareness

Free Psycho-Social counselling

IMPHAL, Mar 20

ಕೋಲಾರ ವಾಹಿನಿ KOLARA VAHINI

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ; ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರಿ

कायद्यावर आधारित शिबीर संपन्न

The Legal Aid Clinic of Kirit P Mehta School of Law NMIMS recently organised a workshop in association with the Ministry of Law and Justice & CEERA-NLSIU

ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା

ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರೆ ಕಾನೂನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

2023 में अखबारों की कतरनें